भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 507

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

इंडिया एआई-इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन

507. श्री मनीश तिवारी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी इंडिया एआई-इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य और विषयगत प्राथमिकताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का तत्काल बाध्यकारी विनियम बनाने के बजाय सुरक्षित, नीतिपरक और समावेशी एआई प्रशासन के लिए मूलभूत आधार नियम निर्धारित करने हेतु इस शिखर सम्मेलन का उपयोग करने का लक्ष्य है;

(ग) इस हेतु एआई सुरक्षा, डेटा प्रशासन, पारदर्शिता, मानवाधिकार और जवाबदेही तंत्र जैसे किन-किन मुख्य फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) क्या यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम और अमेरीकी दृष्टिकोणों जैसे ढांचे के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामंजस्य की संभावना तलाशी जा रही है; और

(ङ) शिखर सम्मेलन के बाद इसके परिणामों को कार्रवाई योग्य नीति, संस्थागत तंत्र या विभिन्न क्षेत्रों में एआई के समान लाभ सुनिश्चित करने वाले विधान में परिवर्तित करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग का लोकतंत्रीकरण कर रही है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

इस संबंध में, सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शासन के लिए एक समावेशी और नवाचार-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है। भारत की एआई रणनीति दुनिया भर के कानूनी ढांचे का अध्ययन करने और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है।

भारत की एआई रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ विनियमन के लिए इसका संतुलित और व्यावहारिक तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण है।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026

इस दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारत, नई दिल्ली में 16-20 फरवरी 2026 तक भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। पहली बार, ग्लोबल एआई समिट सीरीज़ ग्लोबल साउथ में होगी। यह बदलाव एक अधिक समावेशी वैश्विक एआई संवाद की ओर एक व्यापक कदम का संकेत देता है।

शिखर सम्मेलन वैश्विक एआई चर्चाओं में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह यूके एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एआई सियोल शिखर सम्मेलन, पेरिस एआई एक्शन समिट (जिसकी भारत ने सह-अध्यक्षता की), और अफ्रीका पर वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का अनुसरण करता है।

यह दर्शाता है कि शिखर सम्मेलन एक व्यापक वैश्विक संवाद के भीतर स्थित है और जिम्मेदार एआई विकास पर सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देना चाहता है।

सात 'चक्र'

शिखर सम्मेलन की विषयगत प्राथमिकताएं, जिन्हें सात 'चक्र' के रूप में जाना जाता है, इसके प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित करती हैं।

इनमें मानव पूंजी, समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई शामिल हैं।

इन विषयगत क्षेत्रों में एआई सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस, पारदर्शिता, मानव-केंद्रित विकास और जवाबदेही ढांचे जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये चर्चाएं शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों और विचार-विमर्श की रणनीतिक दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संरेखित हैं।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करना है जो तत्काल बाध्यकारी नियम बनाने के बजाय दीर्घकालिक एआई शासन उद्देश्यों में योगदान करती हैं।

****